[श्री युवराज]

भावश्यकता होगी। भापको जान कर भाश्चर्य होगा कि बिहार की सरकार ने तीन-तीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं। तेनूघाट धर्मल पावर स्टेशन जिसको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भौर प्लानिंग कमीशन ने सिद्धान्ततः मान भी लिया है लेकिन उस पर भी स्वीकृति नहीं दी गई है।

मुजफरपुर में एक थर्मल पावर स्टेशन के लिये बिहार सरकार की ग्रोर से सिफारिश की गई थी। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी 1971 से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार के समक्ष पड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापको यह जान कर ताज्जुब होगा कि कहल गांव की ग्रोजना, जिसकी घोषणा पिछले सल में हमारे एनर्जी मिनिस्टर ने की थी ग्रोर जिसे बिहार सरकार ने समर्पित किया था, वह भी ग्राज खटाई में पड़ी हुई है।

इन तमाम बातों की तरफ मैं इस माननीय सदन का ध्यान इसलिये श्राकित करना चाहता हूं कि जिस उत्तर बिहार की श्रयंश्यवस्था का मेरुदण्ड कृषि है, जिस दक्षिणी बिहार में छोटे श्रौर बड़े उद्योग हैं—वहां बिजली की कमी के कारण सारे उद्योग श्रौर खेती बर्बाद होने लगी है। हमारी ये तमाम योजनायें, जिनको बिहार की सरकार ने सम्पित किया है, केन्द्र की शिथिलता के कारण या यों कहा जाये कि प्लांनिंग कमीशन के श्रक्सरों के काम करने के तरीके के कारण उनकी जो श्रयवहारिक प्रिक्रया है उसके कारण, जो बिहार इस देश में सबसे ज्यादा रायल्टी देता है, उसकी सारी कृषि श्रौर सारे उद्योग ठप्य पड़ गये हैं।

इन शब्दों के हाच इस समस्या पर मैं सदन का ध्यान माकृष्ट करना चाहता हूं।

14.56 hrs.

(ii) RESENTMENT DUE TO NON RESUMP-TION OF BHAGALPUR-BIHPUR RAIL AND STEAMER SERVICE

डा० रामजी सिंह (भागलपूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष परि-स्थिति की ग्रीर ग्रापका ध्यान ग्राक्षित करना चाहता हं। श्रभी-श्रभी हम लोगों ने कानपुर में 11 व्यक्तियों की मृत्यु के विषय में सुना था, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं जिस बात का उल्लेख कर रहा है कि वहां ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण या दुखांत घटना होगी, लेकिन भागलपूर जिले में बीहपूर से लेकर भागलपूर तक जो रेल गाड़ी पिछले 85 वर्षों से चल रही थी, न जाने किस कारण से उसको इस साल बन्द कर दिया गया । पिछले 8 महीनों से मैं इस सदन में श्रीर इस सदन के बाहर पत्नों के द्वारा भी सरकार का ध्यान स्नाकृष्ट करता श्रा रहा हूं, लेकिन वह गाड़ी ग्रभी तक नहीं लौटाई गई है। फलस्वरूप उस क्षेत्र में जन-विक्षोभ ग्रीर जन-ग्राक्रोश बहुत वइ रहा है।

10 नवम्बर को वहां लगभग बीस हजार जनता इकट्ठी हुई थी, लोगों ने मांग की कि 85 वर्षों से जो रेलवे लाइन ग्रौर स्टीमर चले ग्रारहेथे, उन को बन्द न किया जाय। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि रेल मंत्री ग्रौर रेलवे के महाप्रबन्धक ने भी यह आश्वासन दिया था-अपने पत्र में, कि वह गाड़ी शीघ्र चालुहो जायगी, लेकिन नौकरशाही न जाने किस कृत्सित षडयंत्र में पड़ कर भ्रभी तक उस गाड़ी को चालू करवाने में ग्रपनी पहल नहीं करवा रही है। पिछले 4 दिसम्बर के दिन वहां के लोगों ने मिल कर ट्रेन का चक्का जाम करने की योजना बनाई थी, जिससे किसी भी समय हिंसा भड़क सकती थी। वहां के प्रतिनिधि बहीं भाये थे, मैंने उन्हें रेल मंत्री जी से मिलाया था, प्रधान मंत्री जी तेभी वेलोग मिले ये और उनके भाश्वासन पर वे लोग रक गये हैं।

मेरा इतना ही कहना है कि छोटी बातों को हम समय रहते नजरम्रन्दाज कर देते हैं तो वह ग्राग भड़क कर कानपूर बन जाती है इसलिए, उगध्यक्ष महोदय, मैं श्रापके माध्यम से सरकार से ग्रौर खास कर रेल मंत्रालय से यह कहना चाहता हूं कि समय रहते इसको जल्द से जल्द चालू करायें। यह मामला देखने में क्षेत्रीय लगता होगा, लेकिन इसका सम्बन्ध उत्तर श्रीर दक्षिण बिहार से है। शायद श्राप को मालूम होगा--गंगा नदी पर रेल का पुल-एक वाराणसी में है, दूसरा बक्सर में है, तीसरा पटना में बन रहा है श्रीर बीया पूल फरक्का में है। इस बीच में गंगा नदी पर कोई पुल नहीं है। दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के सभी जिलों श्रीर भागलपूर तथा उत्तर बिहार के सहरसा, पूर्णिया ग्रीर ग्रासाम से सम्बन्ध रखने वाली केवल यही रेलवे लाइन ग्रौर स्टीमर था। लेकिन इसको बन्द किया जा रहा है। पिछले साल यह छ: महीने तक बन्द रही और इस साल ग्रभी चाल भी नहीं हुई है जब कि इसके बारे में ग्राक्वासन मिला था। उपाध्यक्ष महोदय '''

15.00 hrs.

जनता की इस वाजिब मांग को श्रगर सरकार आश्वासन दे कर भी समय रहते पूरा नहीं करेगी; ग्रीर नौकरशाही की साजिश में पड़ कर ग्रगर वहां कोई भी ध्वंस लीला होगी, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार पर होगी। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ ग्राकषित करना चाहता हुं।

15 or hrs.

MOTION RE: REPORT (1974) OF COMMISSION OF INQUIRY INTO THE DISAPPERANCE OF NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE—Contd.

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the demand to scrap the report of the Khosla Commission is a demand of the people of India and of the people of democratic countries in the world. The Khosla Commission's report should not only be scrapped, but also be burnt to ashes.

It has been proved beyond doubt from facts and figures that that report is not correct. In the Khosla Commission's report it has been stated that the fact that there was an air crash on 18th August 1945 of the plane in which Netaji was travelling, was an evidence that Netaji died in that air crash. But it is not a fact. This was scrutinised by different organizations and by different committees, and it was found baseless.

Mr. Deputy-Speaker Sir, you will remember that the British Government have not accepted any report that Netaji had died. During the time of Lord Wavell-who was the Viceroy of India-he formed three investigation committees and the reports of those committees differed from each other. There were three different opinions found in the reports viz. of the Figgess team, Finney's team and the Combined Services Detailed Intelligence Centre (CSDIC). The reports of these teams stated, and proved that Netaji did not die in the plane crash. They did not accept that position. Whether Netaji is alive or dead, what we want is a proper and true enquiry. We want to have an enquiry committee with the Members of Parliament and experts which should investigate into the matter. You will find very objectionable remarks in Mr. Khosla's report. Those remarks are insulting not only to the Members of this House, but also to the people of India. Netaji was and is the greatest revolutionary in the would, as stated by our late Prime Minister Lal Bahadur Shastri, while unveilling his statue in the Calcutta Maidan. In Mr. Khosla's report, you will find it mentioned that people of some countriesfelt that Netaji was a puppet in the hands of the Japanese. It is a shame. He also said that Netaji was a pawn, he was a quisling, he had no selfrespect and that he had no followers at the end of the war. Isit expected of a Commission, appointed by a civilised government of a country, to make such remarks? The Khosla Commission, I should say with all